मि. सं. 1(93)/ आर्थिक प्रभाग/2014

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(आर्थिक प्रभाग)

नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली

दिनांक 13 मार्च, 2015

<u>विषयः आर्थिक समीक्षा 2014-15 के खण्ड-I से संबंधित शुद्धिपत्र ।</u>

1. आशोधन नीचे की सारणी में दर्शाए गए हैं।

अध्याय सं. पृष्ठ सं.	परिवर्धन
1. **आमुख**	पैरा 3 में अंतिम वाक्य के रूप में - खण्ड 2 अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ गाइड और आंकड़ों के निधान के रूप में कार्य करेगा।
2. **अध्याय 1, पृष्ठ 23**	सारणी 1.2 की पाद टिप्पणी के रूप में बिजली विशिष्ट वर्ग अधिग्रहण (एलीट कैप्चर) भारत में रिहायशी प्रशुल्क सब्सिडी (2015) विश्व बैंक समूह [क्रिस्टी मेयर, सुदेशणा घोष बनर्जी और क्रिस ट्रिम्बल]
3. **अध्याय 1 पृष्ठ 43**	अंतिम पैरा के पहले निम्नानुसार पैरा अन्तः स्थापित किया गया हैः “एक दूसरा लाभ होगा। पिछले कुछ वर्षों में राज्यों का समग्र घाटा लगभग केन्द्र के घाटे से आधा रहा हैः 2014-15 (बजट अनुमान) में उदाहरणार्थ, राज्यों” का संयुक्त राजकोषीय घाटा केन्द्र के 4.1 प्रतिशत की तुलना में स.घ.उ. का 2.4 प्रतिशत अनुमानित था। राज्य वित्तसाधनों के हालियाविश्लेषण के आधार पर हमें पता चलता है कि चौदहवें वित्त आयोग के परिणामस्वरूप राज्यों को अतिरिक्त अंतरण करने से संयुक्त रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों के समग्र राजकोषीय घाटे में स.घ.उ. के लगभग 0.3-0.4 प्रतिशत की कमी आएगी।इसके अतिरिक्त, लगभग सभी राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किए हैं, जिसके तहत उन्हें राजकोषीय अनुशासन को उच्च स्तर पर बनाएं रखने की आवश्यकता

	है जैसाकि घाटे को निम्न स्तर पर रखना। अतः समेकित स्तर पर लोक वित्तसाधनों (केन्द्र और राज्य) में केवल केन्द्र के ही वित्त साधनों की दृष्टि से होने वाले सुधारों की तुलना में कहीं अधिक सुधार होगा।
4. **अध्याय 2 पृष्ठ 45**	खण्ड 2.1 के अंत में अन्तः स्थापित पैरा निम्नानुसार हैः- " अंततः, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की बहुत महत्वपूर्ण लेकिन कम सराही जाने वाली विशेषता है उसका परिपेक्ष्य। 2015-16 में देश (केन्द्र और राज्य) द्वारा किया गया कुल कर संग्रहण का लगभग 62 प्रतिशत राज्यों को प्राप्त होगा जो 2014-15 में लगभग 55 प्रतिशत रहा था। यह आमूल परिवर्तन है। अब यह पूर्णत: आवश्यक है कि भारतीय वित्तसाधनों का आकलन केवल केन्द्र के स्तर पर करने की बजाय समेकित स्तर पर किया जाए। और यहां तस्वीर बिलकुल अलग हो सकती है। यदि राज्यों को प्राप्त होने वाला अतिरिक्त राजस्व का हालिया वर्षों के तरीके से व्यय किया जाता है तो यह संभव है कि समेकित राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 0.2 से 0.6 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है और राजस्व घाटा स.घ.उ. का लगभग 0.4 प्रतिशत कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त समेकित पूंजी व्यय स.घ.उ. का 0.3 और 0.6 प्रतिशत के बीच बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, व्यय पर नियंत्रण और राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता सभी केन्द्र सरकार के स्तर से बेहतर होंगे और केन्द्र सरकार के राजकोषीय लक्ष्यों के बाजार की आशाओं के निकट होंगे।
5**. अध्याय 3 पृष्ठ 54**	सारणी 1.2 की पाद टिप्पणी के रूप में "इलेक्ट्रिसिटी- एलीट कैप्चर रेजीडेंसियल टैरिफ सब्सिडीज इन इंडिया"(2015) विश्व बैंक समूह [क्रिस्टी मेयर, सुदेशणा घोष बनर्जी और क्रिस ट्रिम्बल]

6. अध्याय 10, पृष्ठ संख्या 131	बॉक्स 10.2 के अंत में: ''एफएफसी ने अब इन श्रेणियों का उन्मूलन कर दिया है''।
7. अध्याय 10, पृष्ठ 137	अंतिम पैरा के पहले निम्नानुसार पैरा अन्तः स्थापित किया गया हैः “एक दूसरा लाभ होगा। पिछले कुछ वर्षों में राज्यों का समग्र घाटा लगभग केन्द्र के घाटे से आधा रहा हैः 2014-15 (बजट अनुमान) में उदाहरणार्थ, राज्यों” का संयुक्त राजकोषीय घाटा केन्द्र के 4.1 प्रतिशत की तुलना में स.घ.उ. का 2.4 प्रतिशत अनुमानित था। राज्य वित्तसाधनों के हालिया विश्लेषण के आधार पर हमें पता चलता है कि चौदहवें वित्त आयोग के परिणामस्वरूप राज्यों को अतिरिक्त अंतरण करने से संयुक्त रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों के समग्र राजकोषीय घाटे में स.घ.उ. के लगभग 0.3-0.4 प्रतिशत की कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, लगभग सभी राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित किए हैं, जिसके तहत उन्हें राजकोषीय अनुशासन को उच्च स्तर पर बनाएं रखने की आवश्यकता है जैसाकि घाटे को निम्न स्तर पर रखना। अतः समेकित स्तर पर लोक वित्त साधनों (केन्द्र और राज्य) में केवल केन्द्र के ही वित्त साधनों की दृष्टि से होने वाले सुधारों की तुलना में कहीं अधिक सुधार होगा।

अध्याय संख्या, पृष्ठ संख्या, मूल पाठ	पाठ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें
1. संकेताक्षर डब्ल्यूपीआई थोक बिक्री एसएआरएफईएसआई	 डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक एसएआरएफएईएसआई
2. अध्याय 1 पृष्ठ 2 युद्धोत्तर काल के वर्षों के संबंध में विभिन्न देशों के प्रमाणयह बताते हैं कि भारी भरकम सुधार किसी भी बड़े संकट के दौरान अथवा उसके बाद हुए; (पांचवां पैराग्राफ)	 युद्धोत्तर काल के वर्षों के संबंध में विभिन्न देशों के प्रमाण यह बताते हैं कि भारी भरकम सुधार किसी भी बड़े संकट के दौरान अथवा उसके तत्काल बाद हुए;
3. अध्याय 1, पृष्ठ 3 ''लगभग 12 तिमाहियों के गिरावट के दौर में आर्थिक विकास दर औसतन 6.7 प्रतिशत रही लेकिन 2013-14 से यह औसतन 7.2 प्रतिशत पर बढ़ रही है और यह विकास के नए अनुमानों पर आधारित है।''(पहला पैराग्राफ)	 ''लगभग 12 तिमाहियों के दौर में आर्थिक विकास दर औसतन 6.7 प्रतिशत रही लेकिन 2013-14 से यह औसतन 7.2 प्रतिशत रही है और यह विकास के नए अनुमानों पर आधारित है।''
4. अध्याय—1, पृष्ठ 7 (जैसाकि खंड 1.12 में दर्शाया गया है) इस संबंध में सरकार की कार्रवाई से वस्तुत: कार्बन कर के रूप में सहायता की जा रही है) (दूसरा पैराग्राफ)	 (जैसाकि खंड 1.12 में दर्शाया गया है, इस संबंध में सरकार की कार्रवाई से वस्तुत: कार्बन कर के रूप में पर्यावरण की सहायता की जा रही है)
5. अध्याय—1, पृष्ठ 28 जो कि विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि रेल परिवहन अधिक सस्ता और ऊर्जा किफायती है। (पहला पैराग्राफ)	 "जो कि विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि रेल परिवहन अधिक सस्ता और ऊर्जा किफायती है तथा इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी नुकसान कम होते हैं।
6. अध्याय 1, पृष्ठ 32 ''एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि ऋणों को समाप्त करना,इनमें होने वाली वृद्धि के जितना ही महत्वपूर्णहै''। (दूसरा पैराग्राफ)	''एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि ऋणों को समाप्त करने की प्रभावकारिता इनमें होने वाली वृद्धि के औचित्य जितना ही महत्वपूर्ण है।
7. अध्याय 1, पृष्ठ 33	

(सारणी 1.3, कालम 1) '' 2क: बिना शर्त घरेलू समाभिरूपता '' 2ख: बिना शर्त अंतर्राष्ट्रीय समाभिरूपता ''3: समाभिरूप क्षेत्रों द्वारा संसाधनों का अवशोषण।	'' 2क: देश के भीतर उत्पादकता में गतिशीलता '' 2ख: विभिन्न देशों में उत्पादकता में गतिशीलता ''3: गतिशील क्षेत्र द्वारा संसाधनों का अवशोषण,।
8. अध्याय 3 पृष्ठ 52 (इस भाग के खंड 13 में चर्चित) (पहला पैराग्राफ)	(इस खंड के अध्याय 1के अनुच्छेद 1-13 में चर्चा की गई है)

"394,000 रुपए की राशिमोटे तौर पर वह राशि है जो प्रत्येक परिवार के व्यय को, उस परिवार के स्तर तक, बढ़ाने के लिए जरूरी होगी जो आय वितरण के 35 प्रतिशतता पर है[2]....(अंतिम पैराग्राफ) 'भारत की आर्थिक समीक्षा 2014-15 अध्याय 3 (पाद टिप्पण– 2)'	"394,000 रुपए की राशिमोटे तौर पर वह राशि है जो प्रत्येक परिवार के व्यय को ऐसे परिवार के स्तर तक बढ़ाने के लिए जरूरी होगी जो आय वितरण के 35 प्रतिशतता पर है[2]... 'वित्त मंत्रालय का परिकलन'
9. अध्याय 3, पृष्ठ 55 भारत की आर्थिक समीक्षा 2015, खंड 1, अध्याय 6 (रेलवेपर) (पाद टिप्पण 8)	भारत की आर्थिक समीक्षा 2014-15, खंड 1, अध्याय 6 (रेलवे पर)
10. अध्याय 5, पृष्ठ 81 इस साक्ष्य का निहितार्थ है कि कृषि क्षेत्रको ऋण देना अत्यधिक हो सकता है और यह अधिकतर बड़े किसानों को जाता है। यह कृषि पूंजी निर्माण के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। शायद इसका बड़ा हिस्सा प्रमुख कृषि कार्यकलापों के लिए बिलकुल नहीं जाता है।	इस साक्ष्य का निहितार्थ है कि कृषि क्षेत्रको दिए जाने वाले ऋण की आवंटन प्रणाली में काफी दोष है और यह अधिकतर बड़े किसानों को जाता है। यह कृषि पूंजी निर्माण के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। शायद इसका बड़ा हिस्सा प्रमुख कृषि कार्यकलापों के लिए बिलकुल नहीं जाता है। कृषि ऋण में किन घटकों को शामिल किया है, इस संबंध में एक मूल्याकंन किया जाना अनिवार्य है।
11. अध्याय 5, पृष्ठ 83 'अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक'	'अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक'
12. अध्याय 10, पृष्ठ 129 finmin.nic.in (पाद टिप्पण1)	www.finmin.nic.in

13. अध्याय 10, पृष्ठ 131 '(बाक्स-1 देखें)' (सारणी 10.1) 'यदि टैक्सबायोंसी एक से अधिक है तो कर संग्रहण में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की दर में हुई वृद्धि से अधिक होगी। (पाद टिप्पण 3)	'(बॉक्स 10.1 देखें)' 'यदि टैक्सबायोंसी एक से अधिक है तो कर संग्रहण में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि से अधिक होगी।
14. अध्याय 10, पृष्ठ 132 'अतिरिक्त व्यय क्षमता कोचालू बाजार मूल्यों पर एनएसडीपी या राज्य को अपने कर राजस्व को लाभ प्राप्ति के अनुसार मापा जा सकता है।' (दूसरा पैराग्राफ)	'अतिरिक्त व्यय क्षमता कोचालू बाजार मूल्यों पर एनएसडीपी या राज्य के अपने कर राजस्व की लाभ प्राप्ति के अनुसार मापा जा सकता है।'
15. अध्याय 10, पृष्ठ 135 (पाद टिप्पण 6) 'एसएसए' 'एमपीएलएडी' ईएपी से संबद्ध एसपीए	'सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)' 'स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)' 'विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं(ईएपी)के लिए विशेष सहायता योजना (एसपीए)'
16. अध्याय 10, पृष्ठ 136 'वर्तमान बाजार मूल्य पर एनएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अधिशेष/कमी सारणी 10.4 के कालम 5 में दिखाई गई है.....' (पहला पैराग्राफ)	'वर्तमान बाजार मूल्य पर एनएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अधिशेष/कमी सारणी 10.4 के कालम 5 में दिखाई गई है.....

2. इसे माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रंगीत घोष)

मुख्य आर्थिक सलाहकार के विशेष कार्य अधिकारी

प्रति:

1. भारत सरकार मुद्रणालय